amar 8_Newspro-Template 07-02-2020 18:56 Page 1

अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न रहे...
सरदार वल्लभ भाई पटेल

रेपो रेट में कटौती न करते हुए भी रिजर्व बैंक ने ऑटो, हाउसिंग और एमएसएमई क्षेत्रों को सस्ता कर्ज देने के साथ मौजूदा ब्याज दर पर एक लाख करोड़ की नकदी बैंकों को उपलब्ध कराने की जो घोषणा की है, उसका अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ने की उम्मीद है।

सस्ता कर्ज और ज्यादा नकदी

इस साल की पहली और मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी आर्थिक समीक्षा में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने एकमत से रेपो दर को 5.15 फीसदी पर स्थिर रखा है, तो इसे समझा सकता है, पर केंद्रीय बैंक की सराहना करनी पड़ेगी कि इसके बावजूद उसने कर्ज सस्ता करने के साथ बाजार में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। मसलन, उसने आगामी 31 जुलाई तक नए रिटेल कर्ज को सीआरआर (नकद आरक्षित अनुपात) से मुक्त कर दिया है। इससे ऑटो, हाउसिंग और एमएसएमई क्षेत्रों को रेपो दर में कटौती न किए जाने के बावजूद सस्ता कर्ज तो मिलेगा ही, जुलाई तक कुल जमा का चार फीसदी केंद्रीय बैंक के पास रखने की शर्त में छूट मिलने से बैंक इन क्षेत्रों को ज्यादा कर्ज भी दे सकेंगे। ऐसे ही रिजर्व बैंक ने आगामी 15 फरवरी से बैंकों को लांग टर्म रेपो के तहत एक से तीन साल तक एक लाख करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की है। इसके तहत कर्जदाता मौजूदा रेपो रेट पर ही दीर्घावधि के कर्ज ले सकेंगे। और तीसरे कदम के तौर पर केंद्रीय बैंक ने हाउसिंग क्षेत्र में अटकी हुई परियोजनाएं पूरी करने के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट के परियोजना कर्ज चुकाने की अवधि एक साल बढ़ा दी है। मुद्रास्फीति की अधिक दर को देखते हुए ही रेपो दर में बदलाव नहीं किया गया, कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव तथा दूध व दालों में तेजी के कारण जनवरी-मार्च तिमाही में खुदरा महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय बैंक का लचीला रुख उम्मीद जगाता है। उसका मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के रुख में सुधार आने के कारण जहां निर्यात बढ़ने की उम्मीद है, वहीं रबी फसलों के बाजार में आने से ग्रामीण मांग बढ़ने के अलावा महंगाई में भी कमी आएगी। वैसी स्थिति में कर्ज सस्ता करने की संभावना से रिजर्व बैंक ने इन्कार

नहीं किया है। इसके बावजूद आर्थिक मोर्चे पर बहुत आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, तो इसकी एक वजह बढ़ती महंगाई के अलावा आर्थिक अनुशासन के मोर्चे पर सरकार का ढीला प्रदर्शन भी है : वर्ष 2020-21 में उसे बढ़े हुए राजकोषीय घाटे का दबाव झेलना पड़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के दूरदर्शी उपायों से कर्ज की मांग बढ़ती है या नहीं, यह देखना होगा। आखिर पिछले साल रेपो रेट में लगातार पांच कटौतियां बेअसर ही रही थीं।

अवसरों की सीढ़ी

शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों में स्कूली शिक्षा तक पहुंच काफी बढ़ी है। लेकिन भारत में सीखने का परिणाम बहुत कम है। अगले दशक में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूली शिक्षा छात्र जीवन का अंत नहीं, बल्कि अवसरों की एक सीढ़ी है।

इस नए दशक की शुरुआत करते ही हम शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) की दसवीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो अप्रैल, 2010 में लागू हुआ था। भले ही इस कानून को शासन और सीखने के परिणामों पर सीमित रखने के चलते इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन पिछले दस वर्षों में स्कूली शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की इसकी उपलब्धि से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आरटीई ने इस क्षेत्र में कई हितधारकों के लिए एक आदर्श के रूप में भी काम किया है।

लेकिन अच्छी तरह से लागू होने के बावजूद भारत में सीखने का परिणाम बहुत कम है। शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को शायद ही कभी राजनीतिक प्राथमिकताओं के रूप में देखा जाता है। कम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली के चलते स्वास्थ्य देखभाल या कृषि की क्षमता का अभाव है। लेकिन इन चिंताओं की अब अनदेखी नहीं की जा सकती, खासकर मानव पूंजी के संकट के प्रकाश में, जो बेरोजगारी के आंकड़ों में परिलक्षित होता है। अब तक ऐसे संकटों में सहायता के लिए स्कूली शिक्षा में गहन सुधार के बजाय कौशल विकास मंत्रालय ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए भारत को इस असंतुलन से खुद को बाहर निकालना होगा और शिक्षा को एक व्यापक मानव पूंजी ढांचे के तहत देखना होगा। आगामी दशक में भारतीय शिक्षा क्षेत्र को पैमाने और तत्व, दोनों पर ध्यान देना होगा। एक तरफ सीखने की समस्या का समाधान करना होगा, तो दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को फिर से निर्धारित करना होगा। अतीत में, यहां तक कि सबसे परिष्कृत शिक्षा नीतियां और पाठ्यक्रम ढांचे कमजोर प्रशासन के कारण अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाए। शिक्षा क्षेत्र में शासन के स्तंभों को मजबूत करना निस्संदेह महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने शिक्षा का संचालन करने के तरीके में बड़े बदलाव लाने का बीड़ा उठाया है। इनमें से कई राज्यों में शुरू में स्कूलों का एकीकरण किया गया।

स्कूलों की संख्या में सुधार के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों, अग्रणी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या और इन कर्मचारियों की क्षमता में विकास निर्देशित हस्तक्षेप के लिए जरूरी है। इन सबके साथ सुधारात्मक कदम पर मजबूती से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि छात्रों को ग्रेड स्तर की योग्यता हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके।

राजस्थान में, जहां इंटरनेशनल इनोवेशन कार्प्स ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन और माइकल और सुसान डेल फाउंडेशन के साथ-साथ राज्य शिक्षा विभाग के साथ काम किया, राज्य सरकार ने अपने आदर्श कार्यक्रम के तहत गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचों और हेडमास्टरों व शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता में रखते हुए करीब 10,000 मॉडल सेकेंडरी स्कूल (हर ग्राम पंचायत में एक) विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इन स्कूलों के हेडमास्टरों को बाद में पंचायत शिक्षा अधिकारी के रूप में नामित किया गया और अपने ग्राम पंचायत के अन्य स्कूलों, खासकर एक मॉडल प्रारंभिक स्कूल, को सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। ऐसे प्रयासों से चार वर्ष में शिक्षकों की रिक्तियां 50 फीसदी से घटकर 19 फीसदी पर आ गई और अग्रणी प्रशासन का एक कैडर बना, जो नियमित रूप से स्कूलों की निगरानी करता है। नेशनल एचीवमेंट सर्वे और बोर्ड के नतीजों, दोनों में माध्यमिक स्कूलों के परिणाम में सुधार के संकेत हैं।

अन्य राज्यों में भी इसी तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जैसे, हरियाणा में ग्रे मैटर्स इंडिया के एक मूल्यांकन का अनुमान है कि 119 प्रखंडों में से 94 में छात्र अब ग्रेड स्तर पर योग्य हैं। इसका श्रेय मुख्यमंत्री कार्यालय से चलाए गए सक्षम हरियाणा कार्यक्रम को जाता है, जिसमें कई हस्तक्षेपों के साथ सुधारात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।

ऐसी सफलताओं के आधार पर नीति आयोग और तीन राज्य- ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं झारखंड साथ-ई कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे प्रयासों को बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त नीति आयोग के नवीन स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के 30 में से 14 संकेत शासन प्रक्रिया से संबंधित हैं, जिनमें शिक्षकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, जवबदेही और पारदर्शिता शामिल हैं।

शिक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए राज्य की क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण बदलाव है, और इन उदाहरणों से पता चलता है कि शिक्षा देने की राज्यों की क्षमता कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन उनकी सफलताओं के बावजूद इन्हें शुरुआती बिंदुओं के रूप मे देखना चाहिए। सबसे पहले ये प्रयास सार्वजनिक स्कूल प्रणाली पर केंद्रित हैं। ज्यादा सार्थक बदलाव के लिए सरकार को एक नियामक और शिक्षा में सुविधा प्रदाता के रूप में दिखना अनिवार्य है।

भारत की शिक्षा प्रणाली मानकीकृत और महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम पर केंद्रित है, छात्रों को सीखने के स्तर और उच्च-दांव वाली बोर्ड परीक्षाओं के बजाय उम्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जिसका परिणाम है, जैसा कि अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरन लिखते हैं, यह छंटाई प्रणाली बन गई है, न कि मानव पूंजी प्रणाली। शिक्षा प्रणाली के व्यापक उद्देश्यों को पुनर्परिभाषित करने की खातिर सक्रिय प्रशासनिक तंत्र का लाभ उठाने के लिए एक नई नीति का प्रयोग करना होगा। इसके लिए मूल्यांकन तंत्र के बुनियादी पुनर्रचना की जरूरत होगी, उच्च दबाव वाली परीक्षाओं से ध्यान हटाने के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन और हितधारकों (अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों, अग्रणी प्रशासकों एवं गैर सरकारी संगठनों) के बीच नई भागीदारी की जरूरत होगी, ताकि इन व्यापक उद्देश्यों की दिशा में उनके प्रयासों में तालमेल बिठाया जा सके।

परिणाम पर फोकस निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे व्यापक मानव पूंजी की रणनीति से समर्थित होना चाहिए। कुछ वर्षों में छात्रों की एक पीढ़ी, जो शायद अन्यथा शिक्षा हासिल नहीं कर पाती, आरटीई के कारण स्कूली शिक्षा का एक चरण पूरा कर लेगी। लेकिन अगले एक दशक में शिक्षा नीति की प्रमुख प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि स्कूली शिक्षा छात्र जीवन का अंत नहीं, बल्कि अवसरों की एक सीढ़ी है।

-लेखक हार्वर्ड केनेडी स्कूल से संबद्ध हैं।

रोहन संधु

जीवन में हमेशा यादगार रहेंगे स्पेस के 328 दिन

अपनी कहानी

>> क्रिस्टीना हमॉक कोच

मैं बहुत खुश हूं कि हम नासा के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है, यह प्रगति का संकेत है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का अवसर मिलना वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। पैगी व्हिटसन मेरी आदर्श हैं।

मेरा जन्म अमेरिका के मिशिगन प्रांत में हुआ, वर्तमान में मैं अपने पति के साथ टेक्सास में रहती हूं। बचपन से ही मेरा सपना अंतरिक्ष यात्री बनने का था। शुरुआती पढ़ाई के बाद मैंने डरहम स्थित नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ साइंस ऐंड मैथेमेटिक्स से स्नातक किया, और उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भौतिकी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में परास्नातक किया।

नासा से जुड़ाव

वर्ष 2001 में मैंने जीएसएफसी (गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर) में नासा अकादमी के एक कोर्स में स्नातक किया। इसके बाद 2002 से 2004 तक जीएसएफसी में ही उच्च ऊर्जा खगोल भौतिकी के लिए प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम किया। उस दौरान मैंने नासा के अभियानों में कई वैज्ञानिक उपकरण विकसित किए, जिन्होंने खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन किया। इसी दौरान भविष्य में होने वाले नासा के अभियानों के लिए जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम को मैंने जुलाई 2015 में पूरा कर लिया। इस प्रशिक्षण में हमें अंतरिक्ष सदस्य के लिए जरूरी वैज्ञानिक और तकनीकी ब्रीफिंग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिस्टम, स्पेसवॉक, रोबोटिक्स, फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग के साथ बिना हवा व पानी के भी जीवित रहने का प्रशिक्षण दिया गया।

ध्रुवीय देशों का अनुभव चुनौतीपूर्ण

अमेरिका से प्रायोजित अंटार्कटिक कार्यक्रम में रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम करते हुए मैंने 2004 से 2007 तक, तीन-साढ़े तीन साल आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों की यात्रा में बिताए। अमुंडसेन-स्कॉट साउथ पोल स्टेशन पर सर्दियों के मौसम में करीब -111 डिग्री तापमान में काम पूरा किया। सूरज को देखे बिना महीनों, एक ही चालक दल के साथ, बिना ताजा भोजन के रहकर लंबा वक्त बिताना चुनौतीपूर्ण रहा।

अंतरिक्ष पर महिलाओं की चहलकदमी

जून 2013 में, मुझे नासा के 21 सदस्यीय दल में चुना गया। 14 मार्च 2019 को मैंने बतौर फ्लाइट इंजीनियर नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के लिए उड़ान भरी। मेरे साथ चालक दल में अलेक्सी ओवचिनिन और निक हेग भी शामिल थे। अंततः 18 अक्तूबर 2019 को मैंने अपनी सहयात्री जेसिका मीर के साथ अंतरिक्ष पर चलहकदमी की। हमें इस अभियान के दौरान आइएसएस के खराब पड़े पॉवर कंट्रोलर 'बैट्री चार्ज-डिस्चार्ज यूनिट' को बदलना था। हमने बिना किसी पुरुष सहयात्री के सहयोग के यह काम किया।

कभी इस बारे में नहीं सोचा

जब मैंने आईएसएस के लिए उड़ान भरी, तो सोचा नहीं था कि मैं एक रिकार्ड तोड़ने में सक्षम बनूंगी। मैंने एक ही फ्लाइट में इतने दिन गुजारे। इससे पहले पैगी व्हिटसन ने 289 दिन अंतरिक्ष में गुजारे थे। मैंने अंतरिक्ष में धरती के 5,248 चक्कर लगाते हुए 13.9 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की। अपने मिशन के दौरान मैंने 210 अनुसंधानों में हिस्सा लिया, जो नासा के आगामी चंद्र मिशन और मंगल पर मानव को भेजने की तैयारियों में मददगार होंगे। मुझे पर्वतारोहण, नाव चलाने के साथ फोटोग्राफी करने और घूमने का शौक है, जो मैं अक्सर पूरे करती हूं।

-अंतरिक्ष में एक मिशन पर सबसे लंबा वक्त बिताने वाली नासा की महिला अंतरिक्ष यात्री के विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

फैक्ट फाइल

बैगा जनजाति

>> बैगा महिलाएं

1860 के आसपास बैगा लोगों को जंगलों में देखा गया, और इन्हें जंगली के रूप में वर्णित किया गया।

हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक एंबुलेंस से स्वास्थ्य सुविधा मिलने की वजह से छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति की शिशु मृत्युदर घट गई है। बैगा झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली आदिम द्रविड़ जनजाति है। ये छोटी अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनकी अब भी वन संसाधनों व वनोपज पर निर्भरता बनी हुई है। ब्रिटिशकालीन दस्तावेजों के मुताबिक, 1860 के आसपास बैगा को सबसे पहले जंगलों में अलग जनजाति के रूप में देखा गया, जहां इन्हें जंगली के रूप में वर्णित किया गया। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले के क्षेत्रों में बिंझवार उप-जाति को बैगा जनजाति का सभ्य उप-मंडल माना जाता है। बैगा जनजाति छोटा नागपुर के भुइया जनजाति का एक वंश है। ये सभी आदिवासी समूह इंडो-आर्यन आदिवासी भाषाएं बोलते हैं। बैगा जनजाति के कुल सात उप-मंडल या उप-जातियां हैं, बिंझवार, भरोटिया, रायभिना, कथभाइना, नरोटिया या नाहर, कोंडवान या कुंडी और गोंडवाना। इन आदिवासी समाजों में बहुविवाह की भी अनुमति है। ठाकुर देव बैगा जनजाति के स्थानीय देवता हैं। इसके अलावा, कई हिंदू देवताओं की भी बैगा लोगों द्वारा पूजा की जाती है। गोदना बैगा जनजातियों की मुख्य विशेषता है। बैगा जनजातियों के बीच गोदना सर्दियों के मौसम के आगमन के साथ शुरू होता है और गर्मी के मौसम तक जारी रहता है। कर्मा और सरहुल झारखंड की बैगा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले दो मुख्य त्योहार हैं।

यूरोप की मुसीबत बनते जंगल

यूरोप का करीब 40 फीसदी क्षेत्र जंगलों से आच्छादित है, पर जलवायु परिवर्तन के कारण आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए सोमिनी सेनगुप्त

देर से ही सही, पर जंगलों को अब पर्याप्त महत्व मिलने लगा है। मंगलवार की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 खरब पौधे लगाने के वैश्विक लक्ष्य को अपना समर्थन दिया। उल्लेखनीय है कि विगत जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में प्रतिनिधियों ने 10 खरब पौधे लगाने का संकल्प लिया था। तब कहा गया था कि 10 खरब पौधे लगाकर जलवायु परिवर्तन के संकट को थोड़ा कम किया जा सकता है। जंगल कार्बन को सोखने के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं-वे पृथ्वी को गर्म करने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड का 30 फीसदी हिस्सा सोखते हैं।

लेकिन जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जंगलों के अस्तित्व पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि भूमध्यसागरीय क्षेत्र के सूखे और गर्म वातावरण में जंगल सूखे से भी धीरे-धीरे खत्म हो सकते हैं। या गर्मी बढ़ने पर पेड़ के तने और शाखाएं संचित कार्बन छोड़ सकती हैं, जिससे अचानक ही पूरा जंगल जलकर खाक हो सकता है। ऐसे में, यह प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है कि जलवायु परिवर्तन के बीच

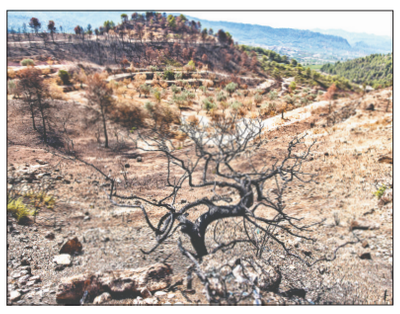

जंगलों को कैसे बचाया जाए। दरअसल यूरोप में जंगलों को बचाने की मुहिम जोर-शोर से छेड़ी जा रही है। इस समय यूरोपीय संघ की करीब 40 फीसदी जमीन वृक्षों से आच्छादित है। इस कारण यूरोप को सर्वाधिक हरीतिमा वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। लेकिन क्षेत्रों में हरियाली अधिक होने से दावानल का खतरा भी ज्यादा है। पिछले साल गर्मी और सूखे की वजह से यूरोप में 1,300 वर्गमील क्षेत्र दावानल की चपेट में आ गया। आंकड़ों के मुताबिक, 2019 में समूचे यूरोप में पूरे दशक की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक क्षेत्र दावानल की चपेट में आए।

पिछले साल यूरोप में जंगल की आग उत्तर में स्वीडन तक फैल गई। जबकि सूखे के साथ-साथ कीड़ों के कारण जर्मनी में जंगलों का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। ब्रिटेन में पिछले साल जंगलों में आग लगने के रिकॉर्ड मामले सामने आए। स्पेन भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी को देखते हुए यूरोपीय संघ ने दावानल को 'खतरनाक और बढ़ता खतरा' बताया है। स्पेन के कैटालोनियन फायर सर्विस में काम करने वाले मार्क कैस्टेलेन्यो ने पूर्वोत्तर स्पेन में दावानल के खतरे को सीधे-सीधे महसूस किया है। मार्क की मां के परिवार के लोग वहां के एक बेहद प्राचीन गांव में कई पीढ़ियों से बादाम उपजा रहे थे। लेकिन जंगल की आग ने सदियों से चल रही उनकी खेती बर्बाद कर दी। बादाम के बगीचे जलकर खाक हो गए। जहां कभी बकरियां चरती थीं, वहां अब दूर-दूर तक जली हुई घास दिखाई देती है।

भविष्य में आग को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने घास और झाड़ियों को पूरी तरह साफ कर दिया है। किसान खेती में भी बदलाव ला रहे हैं, ताकि दावानल के सीजन से पहले अपनी फसल काट सकें। सैंतालीस साल के मार्क ने अपने जीवन में जंगल की ऐसी आग पहले कभी नहीं देखी। वह कहते हैं कि दावानल का मुकाबला करने के बजाय बेहतर यह है कि उसका असर कम करने की कोशिशें की जाएं।

सूत्र

>> ए. वेलुमणि

छोटी पूंजी से भी खड़ी की जा सकती है बड़ी कंपनी

मेरा जन्म 1959 में कोयम्बटूर से 26 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में भूमिहीन किसान परिवार में हुआ था। मेरे पिता अपनी गरीबी के कारण परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे थे। ऐसे में मेरी मां ने पारिवारिक जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया और दो भैंसे खरीदीं। उन भैंसों के दूध से हर हफ्ते पचास रुपये की आमदनी होती थी, जिससे परिवार चलता था। उसी पचास रुपये की आय पर अगले दस वर्षों तक परिवार का गुजर-बसर हुआ। मेरा परिवार इतना निर्धन था कि मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल भी नहीं खरीद सकता था। खैर, 19 वर्ष की उम्र में मैंने बीएससी की डिग्री हासिल की, लेकिन कोई अच्छी-सी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार मैंने कोयम्बटूर की एक छोटी-सी दवा कंपनी में 150 रुपये के मामूली वेतन पर नौकरी कर ली। उस समय तमिलनाडु में एक ग्रेजुएट को चौकीदार से भी कम तनख्वाह मिलती थी। उसमें से पचास रुपये मैं अपने खर्चे के लिए रख लेता था और बाकी घर भेज देता था। चार वर्षों तक उस कंपनी में मैंने नौकरी की, फिर मुझे लगा कि ऐसे में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने उस नौकरी से इस्तीफा दिया और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), मुंबई में नौकरी के लिए आवेदन किया। जब वहां से साक्षात्कार के लिए बुलावा आया,

तो उधार लेकर गया, लेकिन वहां मुझे 880 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। वहां आठ घंटे काम करने के बाद बाकी समय खाली रहता था, इसलिए मैं चार ट्यूशन पढ़ाने लगा, इससे मुझे 800 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने लगी। उसमें से 12,00 रुपये मैं अपनी मां को भेज देता था। मैंने उसे झूठ बताया था कि मेरा वेतन दो हजार रुपये है, क्योंकि मात्र 800 रुपये की नौकरी के लिए वह मुझे गांव नहीं छोड़ने देती। उसके बाद मेरी शादी सुमति से हुई, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करती थी। शादी करने के बाद मैंने नौकरी करते हुए थाइरॉइड बायोकैमिस्ट्री में पीएचडी की और वैज्ञानिक का दर्जा हासिल किया। बाद में मैं बीएआरसी के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल स्थित रेडिएशन मेडिसिन सेंटर में काम करने लगा। पंद्रह वर्षों तक लगातार सरकारी नौकरी करने के बाद मेरे मन में एक बेचैनी-सी होने लगी। मैंने देखा कि जिन्हें मैंने थाइरॉइड का परीक्षण करना सिखाया, वे काफी पैसे कमा रहे हैं और मैं सरकारी वेतन पर संतोष कर रहा हूं। आखिरकार एक दिन मैंने इस्तीफा दे दिया और दो लाख रुपये की पूंजी से थाइरोकेयर नामक कंपनी की स्थापना की। अभी हमारी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 350 करोड़ रुपये है, जिसे अगले दो वर्षों में 600 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है।

कठिन मेहनत, लगन और अपने हुनर के बल पर किसी भी उम्र में की जा सकती है नई शुरुआत और पाई जा सकती है सफलता।

इस हफ्ते के शब्द

रानी रामपाल
भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय हैं।

चेंज (CHANGE)
आयरलैंड में हो रहे आम चुनाव के प्रचार के दौरान यह शब्द इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इसका अर्थ होता है- बदलाव।

विदेशी मुद्रा भंडार

426.42 अरब

डॉलर पर पहुंच गया है देश में विदेशी मुद्रा भंडार, जो अब तक के उच्चतम स्तर पर है, रिजर्व बैंक की जानकारी के मुताबिक।